Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 8, pp 447-449, August, 2026

होर्मुज़ जलडमरूमध्य और वैश्विक तेल आपूर्ति: ईरान–इज़राइल संघर्ष का प्रभाव

धीरज यादव[1], प्रो. कुमुद रंजन[2]

[1] शोधार्थी, [2] राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

सार (ABSTRACT)

फरवरी–मार्च 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध किए गए संयुक्त सैन्य अभियान, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई की मृत्यु हुई, ने पश्चिम एशिया के छद्म-संघर्ष को प्रत्यक्ष युद्ध में बदल दिया। प्रत्युत्तर में ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी रक्षक कोर ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य—जिससे विश्व के समुद्री तेल-व्यापार का लगभग एक-चौथाई तथा वैश्विक LNG व्यापार का लगभग पाँचवां हिस्सा गुज़रता है—से होकर होने वाले नौवहन को बाधित कर दिया, जिसे आधुनिक इतिहास के सर्वाधिक गंभीर ऊर्जा आपूर्ति-आघातों में से एक माना गया है। भारत, जो अपनी कुल तेल-खपत का 85–89 प्रतिशत आयात करता है और जिसका 60 प्रतिशत से अधिक आयात खाड़ी देशों से होता है, इस संकट से विशेष रूप से प्रभावित हुआ।

यद्यपि होर्मुज़ के भू-रणनीतिक महत्त्व पर साहित्य उपलब्ध है, तथापि 2026 के इस वास्तविक संकट का समग्र, भारत-केंद्रित विश्लेषण सीमित है—यही शोध-रिक्तता प्रस्तुत अध्ययन का आधार है। अध्ययन का उद्देश्य होर्मुज़ के भू-रणनीतिक व कानूनी महत्त्व, संघर्ष के घटनाक्रम, वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला पर प्रभाव, तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति, कूटनीति एवं प्रवासी-सुरक्षा पर पड़ने वाले परिणामों का विश्लेषण कर भविष्य की रणनीति हेतु सुझाव देना है। यह गुणात्मक, विवरणात्मक-विश्लेषणात्मक अध्ययन IEA, EIA, बेकर इंस्टीट्यूट तथा भारत सरकार की रिपोर्टों जैसे प्रामाणिक द्वितीयक स्रोतों के त्रिकोणीकरण पर आधारित है, तथा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की समकालीन व्यावहारिक परीक्षा के रूप में एक केस-स्टडी प्रस्तुत करता है।

1.1 पृष्ठभूमि

होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला वह संकरा समुद्री मार्ग है जिसे विश्व की ऊर्जा-व्यवस्था का सबसे संवेदनशील 'चोकपॉइंट' (chokepoint) माना जाता है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर मात्र लगभग 33 किलोमीटर चौड़े इस जलमार्ग से होकर सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन लगभग दो करोड़ बैरल तेल—अर्थात् विश्व के कुल समुद्री तेल-व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा तथा वैश्विक द्रवित प्राकृतिक गैस (LNG) व्यापार का लगभग पाँचवां हिस्सा—गुज़रता है (Ulrichsen & Krane, 2026)। यह जलमार्ग सऊदी अरब, इराक़, कुवैत, क़तर, संयुक्त अरब अमीरात तथा स्वयं ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा-निर्यातक देशों के लिए वस्तुतः एकमात्र समुद्री निकास द्वार है, जिस कारण इसकी सुरक्षा और सुगमता वैश्विक ऊर्जा-सुरक्षा की एक बुनियादी शर्त बन जाती है।

फरवरी–मार्च 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध किए गए संयुक्त सैन्य अभियान—जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई की मृत्यु भी हुई—ने पश्चिम एशिया में वर्षों से सुलग रहे छद्म-संघर्ष को प्रत्यक्ष युद्ध में परिवर्तित कर दिया। प्रत्युत्तर में ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी रक्षक कोर (IRGC) ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले वाणिज्यिक नौवहन को बाधित करना आरंभ किया, जिससे यह मार्ग प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो गया। बेकर इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषण के अनुसार, इस अवरोध ने वैश्विक कच्चे तेल और LNG व्यापार के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को बाधित अथवा पुनर्मार्गित करने पर विवश किया, साथ ही पेट्रोरसायन, उर्वरक, हीलियम और एल्युमिनियम जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात पर भी असर डाला (Ulrichsen & Krane, 2026)। इसे आधुनिक इतिहास के सर्वाधिक गंभीर ऊर्जा आपूर्ति-आघातों में से एक माना गया है, जिसकी तुलना 1970 के दशक के तेल संकटों से की जा रही है।

भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की खपत का लगभग 85 से 89 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है, जिसका एक बड़ा भाग खाड़ी क्षेत्र से होर्मुज़ मार्ग के रास्ते ही प्राप्त होता है (Anantam IAS, 2026; Geojit Insights, 2026)। भारत की संसदीय स्थायी समिति (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इराक़, सऊदी अरब, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से आता है (The Diplomat, 2026)। ऐसी स्थिति में होर्मुज़ जलसंधि संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति-नियंत्रण, विदेश-व्यापार संतुलन तथा प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा—सभी को एक साथ प्रभावित करने वाला बहुआयामी संकट बनकर उभरा है।

1.2 समस्या-कथन (Problem Statement)

यद्यपि होर्मुज़ जलडमरूमध्य के भू-रणनीतिक महत्त्व पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है, तथापि फरवरी 2026 के पश्चात् उत्पन्न वास्तविक अवरोध-संकट—जो पूर्ववर्ती धमकियों और आंशिक व्यवधानों से गुणात्मक रूप से भिन्न है—का समग्र, अद्यतन एवं भारत-केंद्रित विश्लेषण अभी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अधिकांश उपलब्ध अध्ययन या तो विशुद्ध रूप से वैश्विक ऊर्जा-बाज़ार के आर्थिक आयामों तक सीमित हैं, या फिर सामरिक/सैन्य दृष्टिकोण तक केंद्रित हैं। भारत जैसी बड़ी ऊर्जा-आयातक एवं साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाने वाली अर्थव्यवस्था पर इस संकट के आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा-संबंधी प्रभावों का समेकित मूल्यांकन एक शोध-रिक्तता (research gap) प्रस्तुत करता है, जिसे यह अध्ययन भरने का प्रयास करता है।

1.3 शोध के उद्देश्य

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य के भू-रणनीतिक, कानूनी (UNCLOS के अंतर्गत पारगमन-अधिकार) एवं आर्थिक महत्त्व का विश्लेषण करना।
- फरवरी–मार्च 2026 के ईरान–इज़राइल संघर्ष के घटनाक्रम और उसके होर्मुज़ जलसंधि-संकट में परिवर्तित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करना।
- वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति-श्रृंखला, कीमतों तथा शिपिंग-मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति, कूटनीति एवं प्रवासी-सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।
- भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया की समीक्षा कर भविष्य की ऊर्जा-रणनीति हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

1.4 शोध प्रश्न

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य के अवरोध ने वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति-श्रृंखला को किस सीमा तक और किन माध्यमों से प्रभावित किया?
- इस संकट का भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रास्फीति तथा विदेश-व्यापार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा?
- भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को बनाए रखते हुए इस संकट के प्रति किस प्रकार की नीतिगत एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी?
- भविष्य में इस प्रकार के चोकपॉइंट-आधारित संकटों से निपटने हेतु भारत के लिए कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ उपयुक्त हो सकती हैं?

1.5 शोध प्रविधि (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-प्रविधि पर आधारित है। इसमें प्राथमिक आँकड़ों के स्थान पर द्वितीयक स्रोतों का व्यवस्थित उपयोग किया गया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) तथा अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आधिकारिक आँकड़े, राइस विश्वविद्यालय के बेकर इंस्टीट्यूट जैसे नीति-अनुसंधान संस्थानों के प्रकाशन, भारत सरकार की संसदीय स्थायी समिति (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) की रिपोर्ट, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक वक्तव्य, तथा प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं एवं समाचार-विश्लेषण संस्थानों (जैसे The Diplomat, Modern Diplomacy) में प्रकाशित सामग्री सम्मिलित है। तथ्यों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु बहु-स्रोत त्रिकोणीकरण (triangulation) की पद्धति अपनाई गई है।

1.6 अध्ययन का महत्त्व

यह अध्ययन तीन दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। प्रथमतः, यह अकादमिक दृष्टि से होर्मुज़ जलडमरूमध्य संकट (2026) पर उपलब्ध साहित्य में भारत-केंद्रित विश्लेषण की कमी को पूरा करता है। द्वितीयतः, यह नीति-निर्माताओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा, आयात-विविधीकरण तथा संकट-प्रबंधन से संबंधित साक्ष्य-आधारित सुझाव प्रस्तुत करता है। तृतीयतः, यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा को समकालीन भू-राजनीतिक संकट के व्यावहारिक परीक्षण के रूप में प्रस्तुत कर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थियों के लिए एक केस-स्टडी उपलब्ध कराता है।

1.7 अध्ययन की सीमाएँ

चूँकि यह अध्ययन एक गतिशील और अभी भी विकासमान भू-राजनीतिक संकट पर आधारित है, अतः इसमें उपयोग किए गए आँकड़े एवं तथ्य लेखन के समय तक उपलब्ध सूचनाओं तक सीमित हैं और भविष्य के घटनाक्रम के साथ इनमें परिवर्तन संभव है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है; प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण अथवा साक्षात्कार इसके दायरे से बाहर हैं। सैन्य-रणनीतिक विवरणों की गहन तकनीकी विवेचना भी इस अध्ययन का केंद्र-बिंदु नहीं है, जो मुख्यतः आर्थिक, ऊर्जा-सुरक्षा एवं कूटनीतिक आयामों पर केंद्रित है।

संदर्भ सूची (References)

Anantam IAS. (2026, May 31). India and the Iran question: Strategic autonomy under a West Asia war. https://anantamias.com/india-iran-west-asia-autonomy/

Bhandari, A. (2021). India and the changing geopolitics of oil (1st ed.). Routledge.

Geojit Insights. (2026, May 29). Energy security in crisis: The West Asia conflict and implications for India and the world. https://insights.geojit.com/

International Energy Agency (IEA). (2025). Global energy security and oil transit through chokepoints. IEA Publications.

Open Magazine. (2026, August). India's strategic awakening: How the Iran war is reshaping energy security, geopolitics and military doctrine. https://openthemagazine.com/

Singh, A. K., Mishra, S., Bhosale, S. S., Shivhare, S., & Kumari, M. (2026). Energy security and multi-alignment: India's strategic balancing in West Asia. Indian Institute of Public Policy Research (IISPPR). https://iisppr.org.in/

The Diplomat. (2026, March 16). Gulf War 3.0: How is India securing its oil supplies? https://thediplomat.com/2026/03/gulf-war-3-0-how-is-india-securing-its-oil-supplies/

Ulrichsen, K. C., & Krane, J. (2026, March 16). Maritime chokepoints and risks to global shipping and energy security. Rice University's Baker Institute for Public Policy. https://www.bakerinstitute.org/research/maritime-chokepoints-and-risks-global-shipping-and-energy-security

U.S. Energy Information Administration (EIA). (2025). The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint. U.S. Department of Energy.

Wikipedia contributors. (2026). Operation Urja Suraksha. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Urja_Suraksha

भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। (2024)। संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट, दिसंबर 2024।

भारत सरकार, विदेश मंत्रालय। (2026)। पश्चिम एशिया संकट पर आधिकारिक वक्तव्य।